चुनाव मैदान में कोई जीते, मतदान में विकास का मुद्दा जीतेगा...

दिल्ली चुनाव पर ग्राउंड जीरो से विवेक कुमार की पांचवी किश्त

यह रिपोर्ट पाठकों को मिलने तक दिल्ली के चुनाव के लिए वोट पड़ चुके होंगे और सभी को 11 फरवरी को चुनाव परिणामों की घोषणा का इंतजार रहेगा। चुनावी कवरेज के इस आखिरी दौर में मजदूर मोर्चा टीम ने कई विधानसभा क्षेत्र के निवासियों से बात कर अधिक से अधिक इलाकों में पार्टियों की जमीनी हकीकत को जानने का प्रयास किया।

भाई तुम सबकी समस्या है कि सिर्फ भाजपा सांप्रदायिक दिखती है, जबकि अन्य राजनैतिक पार्टियाँ बेशक जो मर्जी करें वे तो दूध की धुली ही लगेंगी- बनारस के रहने वाले 62 वर्षीय रमेश मिश्र बदरपुर में हार्डवेयर की दुकान चलाते हैं। अपना कोट तेजी से उतारते हुए साथ खड़े साथी के हाथों में ऐसे थमाया जैसे हिंदुत्व की लालटेन आजकल 'हिन्दू' हाथ में थमाने का प्रयास राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। मिश्र ने कहा कि केजरीवाल जो खुद को विकास पुरुष कह रहा है क्या वो राजनीति नहीं कर रहा, धर्म के नाम पर लोगों को मुफ्त की तीर्थ यात्रा करा कर। यदि मोदी मंदिर की बात कर दे तो वह सांप्रदायिक कैसे?

मिश्र का समर्थन करते हुए उनके साथी अवधेश ने जोड़ा कि विकास क्या होता है यह केजरीवाल और आप पत्रकारों को बनारस आ कर देखना चाहिए। कैसे सारी संकरी गलियां तोड़ कर मोदी ने गंगा का सौन्दर्यीकरण कर दिया है। स्कूल और अस्पताल केजरीवाल ने बनाये या नहीं बनाये ये तो भगवान् जाने पर मुफ्त दे-दे कर दिल्ली को बर्बाद कर दिया यह मैं जानता हूँ। जहाँ मोदी ने एक तरफ पूरे बनारस की कायाकल्प कर डाली वहीँ केजरीवाल ने दिल्ली को झुग्गियों की खान बना दिया है।

प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के बाशिंदों से अलग राय रखने वाले धीरज भी बदरपुर विधानसभा के निवासी हैं और प्रह्लादपुर में बेकरी की दुकान चलाते हैं। 34 वर्षीय धीरज के मुताबिक केजरीवाल को 70 सीटें आ जाएँ तो भी कोई हैरानी की बात नहीं। धीरज ने केजरीवाल के विरोध में खड़े लोगों को दिल्ली की पुरानी तस्वीरें निकाल कर आज की नयी तस्वीरों से मिलाने की सलाह देते हुए बताया कि, यदि आप दिल्ली से फरीदाबाद की मेट्रो में सफर कर रहे हों और सरिता विहार से लेकर मात्र चार किलोमीटर के सफर में मेट्रो की दोनो तरफ की खिड़की से बाहर देखेंगे, तो लाल-लाल इंटों की बनीं भव्य भवन जो कि दिल्ली सरकार के बनाए स्कूल हैं, दिख जाएँगे। इन स्कूलों को देखने के बाद मोदीभक्त सोचें जरा कि अपनी जिन्दगी में कब बैठे थे ऐसी इमारतों में पड़ने के लिए। इसलिए मेरा और मेरे पूरे मोहल्ले का वोट केजरीवाल सरकार को पड़ेगा।

गोविन्दपुरी कालकाजी विधानसभा में रहने वाले दीपक कुमार पुणे में नौकरी करते हैं। दीपक ने बताया कि उनकी शिक्षा-दीक्षा दिल्ली के सरकारी स्कूल से हुई है। वर्ष 2004 में अपनी स्कूली पढाई समाप्त कर दिल्ली विश्वविद्यालय के रामानुजम कालेज से स्नातक हो गए। पंद्रह वर्ष की इस पढाई में भी कभी ऐसे स्कूल में बैठने का सौभाग्य नहीं मिला। जब भी कालका पब्लिक स्कूल और न्यू ग्रीन फील्ड स्कूल के बच्चों को देखता था तो मैं और मेरे सब साथी खुद को हीन महसूस करते थे। इन स्कूलों की बिल्डिंगों से निकलने वाले बच्चों का आत्मविश्वास हमसे बहुत ऊपर था। पर अब जब सरकारी स्कूल भी वैसे हो गए या यूं कहूँ कि उनसे भी बड़े और बेहतर हो गए तो देखो इन बच्चों का आत्मविश्वास भी वैसा ही हो कर इनके रिजल्ट में दिखने लगा है।

लकड़ी का काम देहाती मजदूरी से करने वाले 45 वर्षीय गोरख चिराग दिल्ली के

निवासी हैं। गोरख ने बताया कि उनके दो बच्चे हैं और दोनों दिल्ली सरकार के स्कूल में ही पढ़ते हैं। पहले किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे जिसका खर्च उठाने में बहुत तकलीफ होती थी, पर अब समाधान उन्हें एक बेहतर सरकारी स्कूल के तौर पर मिला। वोट किसे देंगे और क्यों? केजरीवाल को देंगे पर सिर्फ स्कूल के नाम पर नहीं। केजरीवाल ने स्कूल के साथ-साथ यह जो मोहल्ला क्लिनिक बनाये हैं इसका फायदा गरीब जनता को है।

शर्मा जी के नाम से चिराग दिल्ली में मशहूर दुबले लम्बे कद और बेहद शांतचित दिखने वाले सुरेश की आँखों के नीचे बड़े-बड़े काले धब्बे हो गए हैं। इसके पीछे क्या कारण है, सुरेश ने बताया कि उनकी पत्नी को कैंसर है, इलाज में सब बिक गया। पर दिल्ली सरकार तो फ्री में इलाज का दावा करती है, पहले सरकारी अस्पताल पर खास यकीन नहीं था किसी ने कहा मैक्स साकेत में ले जाओ, तो वही ले गया। इतना पैसा लगा कि गाँव की जमीने बिक गई और अंत में दिल्ली सरकार के जीटीबी अस्पताल ले गया। खैर फिलहाल पत्नी ठीक हैं और दवाएं भी मिल जा रही हैं तो कुछ सुकून हुआ है जिसके कारण काम पर लौट पाया हूँ।

भाई वोट तो तब दूंगा न जब मेरा वोटर आईडी आएगा। गुरमीत ने चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए बताया कि उन्होंने अपना वोटर एड्रेस बदलवाया था। छत्तरपुर में ही चुनाव आयोग वालों का दफ्तर भी है, जहाँ कभी बिजली ही नहीं रहती। जब जाता हूँ, कर्मचारी बाहर धूप सेकते मिलते हैं और कह देते हैं कि जब बिजली आएगी तब बता पाएंगे। तीन दिन चक्कर काटने के बाद पता चला है कि मेरा वोटर कार्ड डाकखाने में है। डाकखाने वाले कह रहे हैं कि नेट नहीं ठीक चल रहा तो हम अभी डिटेल्स नहीं बता सकते। अब आप बताओ क्या ये आम आदमी पार्टी की चाल नहीं है कि जो उसका वोटर न हो उसे वोटर आईडी ही न दे ताकि चुनाव जीत लें आसानी से। कल चुनाव हैं और आज तक मैं वोटर आईडी के लिए धक्के ही खा रहा हूँ।

दिल्ली हाट, आईएनए में हेंडीक्राफ्ट की बारीकियों के तारीफ में कसीदे कसते हुए नीतू ने बताया कि वह हर माह दिल्ली हाट बाजार में दो बार जरूर आती हैं और यहाँ के कारीगरों से हाथ से बनने वाली कला की जानकारियां लेती हैं। जो मुख्य बातें पता चलती हैं उनमे सबसे बड़ा मसला उचित मजदूरी का नहीं मिलना है। दिल्ली सरकार ने न्यूनतम वेतन को लागू करवाकर बड़ा काम किया है। पर क्या सबको न्यूनतम वेतन मिल रहा है? नहीं, मिल तो नहीं रहा, पर कानून बना है तो देर-सबेर लागू भी होगा, कम से कम शुरुआत तो हुई।

मोदी के आने के बाद से ही आज पाकिस्तान और चीन जैसे हमारे दुश्मन देश भारत से घबराते हैं वरना पहले कोई भी हमें आँख दिखाने लगता था। 24 वर्षीय विजय जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं ने यह दावा किया। विजय के अनुसार मोदी का यह कथन कि पाकिस्तान को हफ्ते भर में हरा देंगे कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आज पाकिस्तान की वह औकात नहीं जो हमें कुछ कह सके। अब जब केंद्र में मोदी इतने मजबूत हुए हैं तो दिल्ली में चुनाव जिता कर उन्हें और मजबूत करने की जरूरत है। देश की रक्षा और मजबूती के लिए मेरा वोट मोदी को।

क्या हफ्ते भर में पाकिस्तान को हरा देने से भारत के लोगों को कोई फायदा होगा। इस सवाल पर सीमा जो गुजरात की रहने वाली हैं और अब दिल्ली की वोटर हैं ने कहा, अगर पाकिस्तान को हरा देने से हमारी बेरोजगारी, गरीबी और अन्य समस्याएं समाप्त होती हैं तो कल युद्ध होता, आज ही कर लो और पाकिस्तान को हरा दो। पर क्या ऐसा संभव है, इस प्रकार की फालतू बातें करना देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। मोदी को समझना चाहिए कि ये बातें अपने सड़क छाप नेताओं के लिए छोड़ कर अर्थव्यवस्था पर ध्यान दें। अच्छे काम कैसे करना है वो केजरीवाल से सीख लें।

आया नगर, छत्तरपुर विधानसभा क्षेत्र के निवासी टिंकू, इग्नू में कार्यरत हैं। टूटी और कचरे में डूबी गलियां दिखाते हुए बताया कि आप के एमएलए करतार सिंह तंवर के पास गए थे कि जब सब जगह का काम हो रहा है तो क्यों नहीं हमारी गली बन रही। तंवर ने कहा मोहल्ला क्लिनिक बना दी है अब और क्या चाहते हैं। ऐसे घमंडी नेता को इस बार हरवा कर अपना विरोध दर्ज करेंगे।

शाहीन बाग को मुद्दा बनाने की भरसक कोशिश भाजपा की तरफ से हुई और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने खुद को इस मुद्दे से अलग रख पाने की कोशिश की। कई न्यूज चैनलों ने दिखाया कि शाहीन बाग के नाम पर जो ध्रुवीकरण हुआ उसका फायदा भाजपा को मिल रहा है और जहाँ एकतरफा चुनाव दिख रहा था अब भाजपा भी वहाँ मैदान में आ गई लगती है। यदि ऐसा है तो क्या यह देश के लिया अच्छा है कि धार्मिक उन्माद के रथ पर सवार होकर नेता विधान सभा में पहुंचे और टिंकू जैसों को उसी कीचड़ भरी नाली में छोड़ जाएं।

अपने इस आखिरी दौर की रिपोर्टिंग में हमने पाया की बेशक शाहीन बाग का मुद्दा हिन्दु-मुस्लिम के तौर पर मीडिया में दिख रहा है पर जमीनी हकीकत अब भी स्कूल, चिकित्सा, और आमजन के मुद्दों से ही जुड़ी हुयी है। बेशक बाजी किसी भी दल के हाथ आये परन्तु यह तय है कि मतदान विकास के मुद्दे पर ही होगा। नेता यह बात मानें न मानें पर अमर शायर फैज के शब्दों में कहें तो, "लाजिम है कि हम भी देखेंगे"।

चोरों ने खुद को चौकीदार बना असल चौकीदारों का राशन, कपड़ा तक लूट लिया...

देश के सैनिकों और उनकी लाशों पर राजनीती करने वाली भाजपा सरकार का असल चेहरा क्या है यूँ तो बताने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। फिर भी कई लोग ऐसे घूम रहे हैं जो मान कर चलते हैं कि सैनिकों की असल रक्षा मोदी जी ही कर रहे हैं, ऐसे लोगों को एक नाम मिल गया है आजकल हाल ही में संसद के समक्ष प्रस्तुत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की रिपोट से पता चला कि सियाचिन या अन्य ऊँचे क्षेत्रों में तैनात सैनिकों को प्रदान किये जाने वाले उपकरण कम गुणवत्ता के हैं। यह कैग की रिपोर्ट बजट सत्र के दौरान 3 फरवरी 2020 को संसद के समक्ष प्रस्तुत हुई।

इस संदर्भ में कैग की रिपोर्ट के मुख्य बिंद

- वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2011-18 की अवधि के दौरान खरीद के प्रावधान और प्रदर्शन पर कैग की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार,

- अधिक ऊँचाई क्षेत्रों हेतु कपड़ों और उपकरणों की खरीद में देरी के कारण वर्तमान समय में आवश्यक कपड़ों और उपकरणों की भारी कमी दर्ज की गई है।

- बर्फ में उपयोग होने वाले चश्मे की आपूर्ति में लगभग 62 प्रतिशत से 98 प्रतिशत की कमी देखी गई है।

- सैनिकों को नवंबर 2015 से सितंबर 2016 तक बर्फीले क्षेत्रों में उपयोग होने वाले जूते उपलब्ध नहीं कराए गए थे और जिसके कारण उन्हें उपलब्ध जूतों की रीसाइक्लिंग का सहारा लेना पड़ा।

- इसके अलावा फेस मास्क, जैकेट और स्लीपिंग बैग के पुराने मॉडल खरीदे जाने के कारण सैनिकों को बेहतर उत्पाद प्रदान नहीं किये जा सके।

- सियाचिन या अन्य ऊँचे क्षेत्रों में रहने वाले सैनिकों को उनकी कैलोरी की मात्रा पूरी करने के लिये विशेष भोजन दिया जाता है किंतु विशेष भोजन की सप्लाई में कमी की वजह से जवानों को लगभग 82 प्रतिशत तक कम कैलोरी वाला भोजन दिया जाता है।

- रिपोर्ट के अनुसार, रक्षा प्रयोगशाला द्वारा किये जाने वाले अनुसंधान और विकास के अभाव में आयात पर निरंतर निर्भरता बड़ी है।

- उच्च ऊँचाई वाले क्षेत्रों में सैनिकों की रहने की स्थिति में सुधार के उद्देश्य से हाउसिंग प्रोजेक्ट को एक तदर्थ तरीके से निष्पादित किया गया था। इस संदर्भ में एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था जो कि असफल रहा।

- कैग ने सरकार से भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना में देरी किये जाने पर भी सवाल किया है, ध्यातव्य है कि वर्ष 1999 में कारगिल समीक्षा समिति ने इस विश्वविद्यालय की सिफारिश की थी। इसके निर्माण में देरी के कारण इसकी लागत लगभग 914 प्रतिशत बढ़ चुकी है, गौरतलब है कि मई 2010 में इस प्रोजेक्ट की लागत 395 करोड़ रुपए थी जो संशोधित होकर दिसंबर 2017 में बढ़कर 4007.22 करोड़ रुपए हो गई है।

कैग की रिपोर्ट के मायने

- चूँकि कैग सरकार के व्यय का लेखा परीक्षण करता है, इसलिये उसके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट सरकार की नीतियों की सफलता एवं विफलता की मुख्य संकेतक होती है।

- सियाचीन एवं अन्य ऊँचे क्षेत्रों में सैनिकों को प्रदान की जाने वाली सामग्री और उपकरणों की मात्रा एवं गुणवत्ता में कमी इस क्षेत्र में सरकार की विफलता को प्रदर्शित करती है। इस संदर्भ में सरकार के तर्क

- थल सेना प्रमुख ने कैग की रिपोर्ट के संदर्भ में कहा है कि यह रिपोर्ट 2015-16 से 2017-18 की अवधि की है जिससे यह वर्तमान समय में सेना की स्थितियों का सही मूल्यांकन नहीं करती है, वर्तमान समय में सेना को प्रदान किये जाने वाले उपकरण बेहतर गुणवत्तावाले हैं।

- इसके अतिरिक्त सरकार ने इस संदर्भ में तर्क दिया है कि वर्ष 2017 में बर्फीले इलाकों में इस्तेमाल होने वाले कपड़ों और सामान की मांग में वृद्धि हुई है जिसके कारण इन क्षेत्रों में सैन्य उपकरणों में कमी दर्ज की गई। इसके अतिरिक्त सरकार ने बजट में रक्षा व्यय में कमी को भी बर्फीले एवं ऊँचाई वाले क्षेत्रों में सैन्य सामग्री एवं उपकरणों में कमी का कारण माना है।

मैं देश नहीं बिकने दूंगा के नारे लगाने वाले हमारे प्रधानमंत्री ने सैनिकों के जूते कपडे तक बिक जाने दिए और अब उनकी जीवम बीमा तक बेचने की तैयारी बजट पेश करते समय वितमंत्री ने प्रधानमन्त्री के इशारे से कर दी। सीमा सुरक्षा बल के उच्च अधिकारी ने ये बताया कि फौज में जो भ्रष्टाचार है उसका आंकलन कर पाना भी आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि मीडिया की पहुँच फौज में उतनी आसान नहीं जितनी कि आम दुनिया तक है। इसलिए प्रधानमंत्री एक तरफ फौज का बजट बेशक बढ़ाते हों पर उसके चार गुना अधिक के अनुपात से लूट भी बढाई जा रही है। जबकि सिपाही के नाम का पैसा ऊपर-ऊपर ही खा लिया जाता है। ये वही सिपाही हैं जो गोली से मर रहे हैं और इनके किसान पिता गाँव में फांसी लगा कर। पर वोटों की फसल लहलहा रही है जैम कर।

- साइबर नजर

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 1 डी/2बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06